RAJYA SABHA

Wednesday, the 19th. February, 1975|the 30th *Magha* 1896 *(Saka).*

The House met at eleven of the Clock, Mr. Chairman in the Chair.

OEAL ANSWERS TO QUESTIONS

Setting up of world Hindi University at Wardha

•31. SHHI S. W. DHABE: t
PROF. N. M. KAMBLE:
SHRI K. N. DHULAP:

Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the World Hindi University is proposed to be set up at Wardha; and

(b) if so, what assistance financial or otherwise Government intend to give to the proposed University?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE AND IN THE DEPARTMENT OF CULTURE (SHRI D. P. YADAV): (a) and (b). Government have no Uroposal under their consideration for the establishment of a World Hindi University. However, the Rashtrabhasha Prachar Samiti, Wardha, proposes to set up a Vishwa Hindi Vidyapeeth at Wardha. Government have not been approached to give financial or other assistance in thig connection.

श्री श्रीधर वासुदेव राव धाबे: अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री जी यह बता सकेंगे कि इतना बड़ा विश्व हिन्दी सम्मेलन नागपुर में हुआ, और वर्धा में जिसकी विद्यापीठ का शिलान्यास बाबू जगजीवन राम जी ने किया और जिसके अध्यक्ष श्री कमलापति त्रिपाठी जी थे, जिसमें यह कहा गया है कि हिन्दी विद्यापीठ पूरी दुनिया में हिन्दी के प्रचार के लिए और उसको अन्तर्राष्ट्रीय स्थान दिलाने के लिये कार्य करेगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन जो नागपुर और वर्धा में शिलान्यास हुआ उसके बारे में सरकार को क्या जानकारी है और क्या सरकार उसके प्रपोजल्स को मंजूर करने जा रही है ?

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रपोजल्स की स्पष्ट रूपरेखा हमारे पास अभी तक आयी नहीं है । माननीय सदस्य ने जो कुछ भी अखबारों में देखा और हमने भी जो उसका लिटरेचर आया है उसका अध्ययन किया है, उसी आधार पर हमने यह बात कही है कि जहां तक हिन्दी के विकास का सम्बन्ध है, सरकार उसके लिये प्रयत्नशील है ।

श्री श्रीधर वासुदेव राव धाबे: मैं जानना चाहता हूं कि अगर प्रपोजल्स उनके पास आ जायं तो इस साल में वह उनके लिए कोई पैसा देने का प्रयत्न करने वाले है ?

श्री डी० पी० यादव: अभी तक प्रपोजल्स नहीं आये है । आने पर हम विचार करेंगे ।

श्री नरेन्द्र मारुत राव कांबले : There are e ome arrangements in foreign countries. There are «ome cells or departments conducted for teaching Hindi. But text-bookg or even other publications are not avila-ble to them.

तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस बात का वह कुछ प्रयत्न करेंगे कि उन किताबों का कुछ प्रबन्ध हो ?

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, हमारा प्रयत्न जारी है और जारी रहेगा ।

fThe question was actually asked on the floor of the House by Shri S. W. Dhabe.

श्री कृष्ण राव नारायण धुलप : क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कोशिश करेंगे कि हिन्दी भाषा बोलने वाले लोग संसार में कितने हैं और खास कर मारिशस, घाना, गियाना, ट्रिनिडाड, सरिनाम, मलेशिया, कीनिया और फिजी, इन देशों में जो हिन्दी भाषी लोग हैं उनके लिए हिन्दी पढ़ने लिखने और बोलने की शिक्षा देने के लिए क्या कोशिश हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है और खास कर यूगं स्लाविया, ईरान, इजराइल, वेस्ट इण्डीज, रूमानिया और श्रीलंका में जो लोग हिन्दी की शिक्षा पाना चाहते हैं उनकी किताबों के बारे में सरकार की तरफ से क्या हो रहा है और दूसरी बात यह कि संसार में जितनी भाषायें बोली जाती हैं चाइनीज और इंगिलश को छोड़ कर, उनमें सबसे ज्यादा हिन्दी भाषा बोलने वाले लोग हैं तो यू० एन० ओ० की भाषा क्या हिन्दी हो सकती है ? यदि हां, तो उसके लिये क्या कोशिश हो रही है ?

MR. CHAIRMAN: The question before the House is whether there should be a World Hindi University or not. Mr. Minister, if you can reply, you can do so.

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, जहां तक विदेशियों को हिन्दी पढ़ाने का सवाल है, दिल्ली में हमारी एक संस्था है जहां पर्याप्त साधन हैं और जितने विदेशी हमारे पास आते हैं, मारिशस से आते हों या घाना से आते हों, उनको पढ़ाने के हमारे पास पर्याप्त साधन हैं । हमारी नोटिस में किताबों की कमी नहीं आई है और माननीय सदस्य अगर ऐसा बतायेंगे तो किताबों की कमी नहीं रहने दी जाएगी ।

श्री कृष्णराव नारायण धुलप : संसार में जितनी भाषायें हैं वह चाइनीज और अंग्रेजी भाषा को छोड़कर हिन्दी भाषा भाषी लोग ज्यादा हैं । तो यू० एन० में हिन्दी भाषा बनाने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

(No reply)

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सभापति जी, कुछ दिन से मैं यह देख रहा हूं कि जान-बूझकर शिक्षा मंत्रालय हिन्दी और संस्कृत की उपेक्षा कर रहा है । मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि क्योंकि यह इस देश की जनभाषा है, अगर कोई मंत्रालय या वरिष्ट मंत्री यह कल्पना करता हो कि उसकी उपेक्षा करने से किसी जनभाषा की उपेक्षा हो जाएगी तो वह स्वप्नों के संसार में रहता है । मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इसी सदन में और दूसरे सदन में भी कई बार यह चर्चा हुई और सरकार ने सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार किया कि दक्षिण भारत में हिन्दी माध्यम का एक विश्व-विद्यालय खोला जाए । कुछ दिन पहले उस्मानिया विश्वविद्यालय को हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय बनाने की चर्चा थी, वह भी स्थगित हुई । फिर दोबारा कर्नाटक गवर्नमेंट की ओर से यह मांग हुई कि गुलबर्गा में एक हिन्दी माध्यम का विश्वविद्यालय खोला जाए, कर्नाटक सरकार उसके लिए भूमि देने को तैयार थी लेकिन फिर केन्द्रीय सरकार ने उसकी उपेक्षा की । अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके द्वारा राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति वर्धा को कि सरकार की उपेक्षा के बावजूद भी उन्होंने स्वयं निजी प्रयासों से जहां गांधी जी का आश्रम था, एक विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना की है । शिक्षा मंत्रालय अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर रहा है कि हमारे पास कोई अप्रोच नहीं हुई है । एक केन्द्रीय मंत्री माननीय श्री जगजीवन राम ने उसका शिलान्यास किया और श्री कमलापति त्रिपाठी ने उसकी अध्यक्षता की।इतना बड़ा विश्व हिन्दी सम्मेलन वहां पर हुआ और शिक्षा मंत्रालय ऐसी बात कर रहा है कि उनको कोई जानकारी नहीं । मैं जानना चाहता हूं, आपके माध्यम से कि यह इतने बड़ी जिम्मेदारी की बात है, जो काम शिक्षा मंत्रालय का है, जिसको वह लोग करने के लिए जा रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय का कोई मंत्री वहां नहीं गया स्वयं शिक्षा मंत्री

नहीं गए । इतना बड़ा हिन्दी सम्मेलन हुआ उसकी शिक्षा मंत्रालय ने उपेक्षा की या नहीं ?

SHRI G. LAKSHMANAN: For a Hindi medium university the demand should come from the non-Hindi speaking people, and not from those who are in the Hindi-speaking areas.

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, माननीय प्रकाशवीर शास्त्री जी को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारे मंत्रालय के द्वारा न हिन्दी और न संस्कृत की उपेक्षा हुई है और न होगी । हम अपनी पूरी ताकत के साथ हिन्दी के विकास के लिए जो भी मुद्दे हमारे पास आयेंगे, मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि, उन पर पूरी तरह से अमल किया जाएगा और विद्यापीठ में जिन चीजों की आवश्यकता होगी वह पूरी की जायेंगी । मान लिया कोई डुप्लीकेट प्रोग्राम आ गया उस पर पैसे खर्च करने के लिए कहें तो यह ठीक नहीं, लेकिन कोई नयी, मौलिक चीज आयगी हिन्दी के विकास के लिए तो मैं आश्वासन देना चाहूंगा शास्त्री जी को कि उसके ऊपर पूरी तरह से सरकार विचार करेगी ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : सभापति जी, मैं जान-बूझकर दोबारा बाधा नहीं डाला करता । मैं श्री यादव जी के विचारों और उनके कार्यों का बहुत सम्मान करता रहा हूं, लेकिन मैं शिक्षा मंत्री के नाते से आपसे जानना चाहता हूं कि आपका यह कर्तव्य नहीं है कि दो दो केन्द्रीय मंत्री जिस समारोह में उपस्थित हैं और केन्द्रीय मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा जिसका शिलान्यास किया जा रहा है, जो काम केन्द्रीय सरकार को करना चाहिए था, वह राष्ट्रभाषा प्रचार समिति स्वयं करने जा रही है, तो आपको अपनी इस भूल का प्रायश्चित करते हुए स्वयं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से पूछना चाहिए कि क्या आपकी योजना है, केन्द्रीय सरकार इसमें क्या सहयोग कर सकती है बजाये इसके कि वह कुछ कहेंगे तो हम विचार करेंगे । यह विचार शिक्षा मंत्रालय की दृष्टि से शोभाजनक नहीं है ।

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, देश के मानस पटल पर यह बात नहीं जानी चाहिए कि हम हिन्दी या संस्कृत की उपेक्षा कर रहे हैं । पुनः मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जब तक कोई ठोस प्रोग्राम हमारे पास नहीं आ जाता है, हम इस काम को कैसे कर सकते है ।

SHRI A. G. KULKARNI: Why you are not taking action?

श्री डी० पी० यादव : जिस संस्था को हमारे मंत्रिमंडल के दो वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त है, हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम उस में अधिकाधिक मदद करने की कोशिश करेंगे ।

श्री कृष्ण कांत : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब विश्व हिन्दी सम्मेलन नागपुर में हुआ था वहां पर एक प्रस्ताव पास किया गया था कि यू० एन० ओ० में हिन्दी भाषा होनी चाहिए, क्या यह सत्य है मारिशस, स्वीडन और बहुत से विदेश के प्रतिनिधियों ने कहा कि पहले अपन यहां तो हिन्दी चलाइए तभी दूसरी जगह की बात करिए ? शास्त्री जी ने भी यह बात उठाई और यह बड़े शर्म की बात है कि विदेश के प्रतिनिधियों ने यहां यह बात कही कि हिन्दी को ठीक तरह से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और आप कहते हैं कि 27 साल से हम कर रहे हैं । आज स्थिति यह है कि हमारी सरकार विदेशियों के सर्टिफिकेट पर चलती है, यह शर्म की बात है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि युनाईटिड नेशन में आपके जितने प्रतिनिधि जाते हैं, भारत के जितने प्रतिनिधि, सरकारी असफर जाते हैं वे हिन्दी नहीं जा ते हैं, वे अंग्रेजी में बात करते हैं । मेरा कहना है कि कम से कम वहां हिन्दी जानने वाले

भेजने चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि आज ही यादव जी, बाबू जगजीवन राम और कमलापति त्रिपाठी जी से मिल कर यह तय करें कि उस विश्वविद्यालय के लिए जितनी ग्रांट, जितनी मदद चाहिए उसके लिए कोशिश करेंगे, क्या इस प्रकार का आश्वासन आप इस सभा सदन में देने को तैयार हैं ?

आखिरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गांधी जी ने मरने से पहले एक बात कही थी कि हिन्दुस्तान आजाद हो गया और मैं जानता नहीं कितनी देर जिन्दा रहूंगा । लेकिन अगर मैं जिन्दा रहा तो एक काम करना चाहता हूं क्योंकि वह काम मेरे मरने के बाद नहीं हो सकता और वह काम है सब भाषाओं को एक अतिरिक्त लिपि में, देवनगरी लिपि में लिखना । यह गांधी जी की आखिरी नसिहत थी कुछ करने के लिए । उनका कहना था कि बाकी लिपियां चलती रहें इसमें मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन सब भाषाओं की एक अतिरिक्त लिपि देवनागरी लिपि होनी चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि अगर सरकार हिन्दी की बात करती है तो इस बारे में क्या सोच रही है ।

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, मैं विश्वास करता हूं कि अगले सभी प्रश्न और उत्तर में कृष्ण कांत जी हिन्दी का प्रयोग करेंगे । हिन्दी में बोलेंगे और हिन्दी में ही उत्तर मांगेंगे । बाकी के जो सुझाव हैं उन सब का मैं शास्त्री जी को जवाब दे चुका हूं, इसमें कोई नई चीज नहीं है ।

श्री कृष्ण कांत : मैंने तो सीधा सा सवाल किया, यह शास्त्री जी का सवाल नहीं था । मैंने यह पूछा कि क्या आज ही यादव जी बाबू जगजीवन राम और कमलापति जी से बात करेंगे कि इस बारे में आगे कुछ करना है ।

SHRI G. LAKSHMANAN: Point of order.

MR. CHAIRMAN: No point of order during Question Hour.

(Interruptions)

DR. R. K. CHAKRABARTI: Sir, ... *(Interruptions).*

MR. CHAIRMAN: AH of you are interested in Hindi, I know.

SHRI RABI RAY: Interested in our mother tongue.

MR. CHAIRMAN: All right, I am also interested. But the question to be answered by the hon. Minister is whether the Government is prepared to give financial assistance for starting **a** Viswa Vidyalaya there or not. It is a restricted question. But you are covering the entire field of Hindi. It is difficult for me to allow supple-mentaries.

SHRI A. G. KULKARNI: To tka question of Mr. Krishan Kant, let Mr. Yadav reply "yes" or "no". Ha is avoiding a reply. Please direct him to reply.

श्री कृष्ण कांत : मैं श्री यादव से चाहता हूं कि नूरुल हसन यहां बैठे हैं और कमलापति जी दिल्ली में ही है उनसे बात करके उस विश्व-विद्यालय के बारे में सहायता देने के लिए आज ही आश्वासन दें ।

SHRI A. G. KULKARNI: To the restricted question let him reply. Please direct him to say that. He ha_3 not replied to your restricted question.

MR. CHAIRMAN: Please wait. I_3 it possible for the hon. Minister to reply specifically yes or no? If **you** are not in a position, you can say it is not possible.

श्री डी०पी०यादव : श्री कृष्ण कांत जी से नमतापूर्वक मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बबू जगजीवन राम जी हमारे मंत्रि-मंडल के वरिष्ठतम सदस्य हैं और उनकी सलाह मुझे और मेरे मंत्रालय को सदैव मान्य होती है और भविष्य में भी होती रहेगी ।

SHRI A. G. KULKARNI: On a point of order. Has he now replied to the question specifically?

SHRI UMASHANKAR DIKISHT: The questions and answers on this issue seem to give the impression that the university or the institution which is now . . .

श्री रवी राय : आप हिन्दी में बोलिये ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : सब लोग समझ सकें, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह असर पड़ रहा है कि जो संस्था खुली है उसको स्वयं सरकार के पास सहायता के लिए जाने में कोई संकोच है । मैं चाहता हूं कि ऐसा संकोच नहीं होना चाहिए । आप अगर इस तरह की जिद करते हैं कि वह तो कहें कि हम मांगेंगे नहीं और हम कहें कि हम सहायता जरूर देंगे तो यह कोई उचित परिस्थिति नहीं है । श्री कृष्ण कांत जी हों या कोई अन्य हों, उनसे हम बात कर सकते हैं । उस संस्था वालों ने कोई अच्छी योजना बनाई हो तो वह योजना यहां भेजी जा सकती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उस योजना पर सरकार विचार कर सकती है ।

SHRIMATI SUMITRA G. KULKARNI: I come from that town. It is a question of my grand-father's association. My family stays in the town of Wardha. Naturally I would like to be interested in the town of Wardha.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, इनको तो प्रश्न पूछने का मौका दिया जाना चाहिए ।

MR. CHAIRMAN: Let him put his supplementary.

SHRI G. KAKSHMANAN: There is a feeling that Hindi which is one of the national languages of India is given a preferential treatment with regard to the affairs of the Indian people. Therefore, intsead of setting up a university for a particular national language of India, in the interest of integration and in the interest of unity of this country, will the Government consider starting a university for all the national languages of India.

PROF. S. NURUL HASAN: Although the question does not arise, I would like to 'make only one submission. I would like to draw the attention of the House to the special obligation of the Government of India to promote the cause of Hindi under article 351 of the Constitution.

श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी : सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा वर्धा में जिस हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, चूंकि वह शिक्षा मंत्रालय से संबंध विषय है, इसलिए उसके संबंध में पूरी जानकारी भी शिक्षा मंत्रालय को ही देनी चाहिए और मैं यह जानना चाहती हूं कि माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि उस विश्वविद्यालय के संबंध में पूरी पूरी जानकारी क्या है और उसके लिए क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ? मैं यह भी कहना चाहती हूं कि चाहे वह विश्वविद्यालय स्वतंत्र रूप से बना हो, लेकिन आखिरकार उस संबंध में पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय की है, इसलिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा वर्धा में स्थापित किये गये विश्वविद्यालय के संबंध में पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय को लेनी चाहिए और उसके संबन्ध में पूछे गये प्रश्नों की पूरी जानकारी भी सदन को देनी चाहिए ।

MR. CHAIRMAN: That, I think, has been replied to. Or, do you want to renlv to it again?

श्री डी० पी० यादव : सभापति जी, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा एक स्वयंसेवी संस्था है जिसको भारत सरकार के

शिक्षा मंत्रालय से काफी रुपया अनुदान के रूप में मिलता है और उसकी इस संबंध में कोई शिकायत भी नहीं रही है कि रुपये की कमी की वजह से उसका कोई काम रुका हो। यह समिति अपने प्रांगण में एक विद्यापीठ बनाना चाहती है। और जैसा कि हमारे माननीय मंत्री दीक्षित जी ने कहा, हम उस पर अमल करेंगे।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय मंत्री महोदय ने कभी इस सदन में आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार हिन्दी की उपेक्षा नहीं कर रही है और न ही करेगी, और हम चर्चा कर रहे हैं विश्व हिन्दी परिषद् की। करीब 27 साल से हिन्दी प्रचार की चर्चा चल रही है लेकिन अभी तक दक्षिण भारत में हिन्दी का जितना प्रचार होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कई प्रपोजल्स आपके सामने आए हिन्दी युनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए हैदराबाद में और कर्णाटक में। उसके लिए आपने सोचा नहीं। तो जब आपका यह रद्दोअमल है, यह रिऐक्शन है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं हिन्दी की उपेक्षा आप नहीं कर रहे हैं और हिन्दी का प्रचार कर रहे हैं ? अगर हिन्दी का प्रचार करने की आज जरूरत है तो दक्षिण भारत में उसकी खास जरूरत है और दक्षिण भारत के लोग यह कहते हैं कि हम हिन्दी चाहते हैं और हिन्दी लाइए, हिन्दी का प्रचार कीजिए। अगर आप हिन्दी की युनिवर्सिटी नहीं खोलना चाहते हैं तो हिन्दी प्रचार करने की क्या बात कर रहे हैं ?

SHRI G. LAKSHMANAN: Sir, the peopxe of Tamil Nadu ^do not want Hindi. ... (Interruptions) . . . The people of Tamil Nadu do not want Hindi.

MB. CHAIRMAN: He has not pleaded for that.

श्री डी० पी० यादव : अध्यक्ष जी, मैं पुनः दुहराना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जो कर्नाटक से आते हैं उन्होंने जो यह कहा कि दक्षिण भारत में हम हिन्दी प्रचार में ज्यादा सक्रिय नहीं हैं, तो मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी योजना प्रत्येक हाई स्कूल में— कम से कम एक हिन्दी शिक्षक नान्-हिन्दी स्टेट्स में देने की है। इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि हम इस ओर सक्रिय हैं।

MR. CHAIRMAN; The question was whether the Government was considering the proposal.

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने यह नहीं कहा कि हिन्दी नहीं सिखायी जा रही है। मेरा सवाल यह है कि हिन्दी युनिवर्सिटी के बारे में जो प्रपोजल्स साऊथ इंडिया से, दक्षिण भारत से, आ रहे हैं उन पर आप क्यों गौर नहीं कर रहे हैं, क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कम से कम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हिन्दी युनिवर्सिटी दक्षिण भारत में स्थापित करने के लिए क्या आपके पास कोई सुझाव है ?

SHRI VISWANATH MENON: Sir, paying lip service to Hindi will not be helpful to that language. The honourable Minister was speaking a lot about spreading Hindi. I am coming from the State of Kerala where Hindi is being taught in all the schools compulsorily right from 1949 onwards from the Fifth Standard to the Tenth Standard. Now, Sir, the latest development is that the Hindi Teacher Trainees, who are being trained in Trichur, Kerala, are not being paid a single pie by way of stipend. The Central Government has to bear this. Their period will be over on the 25th of this month. I have written to the honourable Minister and also to the other people concerned. Many MPs also have written to the honourable Minister. But they have not paid a single pie though

they are talking about starting a Hindi University. When they talk about starting a Hindi University, at least they should do something for these Teacher-Trainees and they should try to pay at least their stipend money and they should act on their promises. My question is whether the honourable Minister will send this money to those people before the 25th of this month.

SHRI RABI RAY: Let him reply to this question, Sir.

MR. CHAIRMAN: Really this is not a supplementary arising from the main question.

SHRI VISWANATHA MENON: Sir, I want a reply from the Minister. Let him do this before he starts a Hindi University.

SHRI D. P. YADAV: Sir, this does not arise out of the main question... *(Interruptions).*

MR. CHAIRMAN: Next question.

SHRI VISWANATHA MENON: Sir, I could not hear him. What was his reply?

MR. CHAIRMAN: He says that this supplementary does not arise out of the main question.

SHRI VISWANATHA MENON: Even the mass petitions by the students are before him and I have also written to him about this about three months back.

MR. CHAIRMAN; That is all right.

SHRI MONORANJAN ROY: At least let him reply to the question about the payment to the teachers.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, आपने मुझ को कहा था कि इस पर प्रश्न करने का मौका देंगे । माननीय शिक्षा मंत्री को और तमाम सम्मानित सदस्यों के प्रश्नों को सुनकर मेरे मन में एक पूरक प्रश्न आ रहा है ।

सरकार यह कहती है कि वह हिन्दी के विकास के लिए तैयार है और 351 अनुच्छेद में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के मुताबिक नागरी लिपि और हिन्दी में तमाम राष्ट्र की भाषाओं को समेट कर के उसकी वृद्धि करना है और सब भाषाओं को ले लेना है । मैं यह जानना चाहता हूं कि आजादी के 27 साल बाद भी इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार इस सदन में सत्य बोलना चाहती है तो मैं यह पूछना चाहता हूं, कि सरकार के जितने भी विभाग हैं हर विभाग में जो हिन्दी में काम करता है, लिखता है, उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है । हिन्दी में काम करने वाले को कम पैसा दिया जाता है और अंग्रेजी में काम करने वाले को ज्यादा पैसा दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है ? जो लोग हिन्दी विषय में जानकारी ज्यादा रखते हैं और जो लोग अंग्रेजी के विषय में जानकारी कम रखते हैं, तो भी अंग्रेजी वालों को ज्यादा पैसा दिया जाता है और हिन्दी वालों को कम पैसा दिया जाता है । तो मैं इस बात का माननीय मंत्री जी से कारण जानना चाहता हूं कि इस तरह की बात क्यों हो रही है ?

क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि हिन्दी और अंग्रेजी में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जायेगा और राष्ट्र की किसी भी भाषा के साथ भेद नहीं किया जायेगा ? जो व्यक्ति अपने विभाग में अपनी भाषा में काम करता हो और उसी विभाग में जो अंग्रेजी में काम करता हो उनको बराबर की तनख्वाह मिलनी चाहिये । तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह कोई इस सम्बन्ध में कानूनी व्यवस्था बनायेगी ? चाहे विरोधी पक्ष के लोग हों,

चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों जो हिन्दी या मातृभाषा को जानता है वह अपनी ही मातृभाषा में बोले और अंग्रेजी में सार्वजनिक ढंग से न बोले । जो हिन्दी के बड़े भारी समर्थक हैं जो हाउस के अन्दर हमेशा हिन्दी हिन्दी की रट लगाते रहते हैं वही लोग इस सदन में अंग्रेजी में बोलते हैं । ऐसा क्यों ? जो हिन्दी के जानकार हैं और अंग्रेजी बोलते हैं वे एक तरह से हिन्दी की तौहीन करते हैं। सरकार की ओर से ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि जो हिन्दी जानते हैं वे कभी भी अंग्रेजी में न बोलें ।

श्री डी० पी० यादव : श्रीमन्, यह तो आपके विचारार्थ के लिए है ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने अनुच्छेद 351 के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ? एक ही विभाग में जो व्यक्ति हिन्दी में काम करता है उसको तो कम तनख्वाह मिलती है और जो अंग्रेजी में काम करता है उसको ज्यादा तनख्वाह क्यों मिलती है ? जिन लोगों की हिन्दी मातृभाषा है वे अंग्रेजी में न बोलें क्या सरकार इस तरह की कोई व्यवस्था करेंगी ?

MR. CHAIRMAN: That he will consider.

PROF. S. NURUL HASAN: If the hon. Member were to give notice as to the steps that have been taken by the Central Government to promote the cause of Hindi by my Ministry..

SHRI RABI RAY:.... and the Indian languages, too...

PROF. S. NURUL HASAN: I will be very glad to furnish the information.

Food production

*32. SHRIMATI SAVITA BEHEN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleaaed to state:

(a) whether a comprehensive programme for increasing food production by at least 35 per cent during the Fifth Five Year Plan period has been drawn out;

(b) if so, what are the details thereof and what is the total estimated outlay of the programme; and

(c) what is the actual food production during 1973-74 and the estimated food yield during the current year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) to (c). A statement is lai^ on the Table of the Sabha.

Statement

(a) and (b). In the Draft Fifth Five Year Plan, it is envisaged to increase the production of foodgrains from an assumed base level of 114 million tonnes in 1973-74 to 140 million tonne$_s$ by 1978-79. This implies an increase of 22.8 per cent over the period of five years. The main features of the programmes for increasing crop production including foodgrains during the Fifth Five Year Plan are: extensions of cropped areas, extension of area under the high-yielding varieties, expansion of irrigation facilities, a substantial step-up in the use of chemical fertilizers, improved seeds and pesticides, command area development, intensification of problem-oriented research and strengthening of extension of effort and institutional arrangements for credit, marketing and input supplies.

In the Draft Fifth Five Year Plan, for agriculture, irrigation flood control, trade and storage, an outlay of